



2026:AHC:48108

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी याचिका सं - 558/2026

फूलचंद

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उप निदेशक चकबंदी एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आनंद यादव, मुकेश सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय क्रमांक - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका, अंतर्वस्तु के रूप में, निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"न्यायालय परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करे, जो प्रतिवादी सं.2/

चकबंदी अधिकारी, फूलपुर, आजमगढ़ को आदेश दे कि वह मामला सं. 560186/2024 (फूलचंद

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



और अन्य बनाम भूवाल) में पुनर्विचार/पुनर्स्थापन आवेदन की कार्यवाही, उत्तर प्रदेश भू-संरक्षण अधिनियम, 1953 की धारा 9-ए के अंतर्गत, गाँव- मौजा- कुशमहरा, परगना- कौरिया, तहसील- बूदनपुर, जिला- आजमगढ़, जो विद्वान चकबंदी अधिकारी, फूलपुर, आजमगढ़ के न्यायालय में लंबित है, का शीघ्रता से माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय करे।”

3. राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले को शीघ्र निर्णीत करने का निर्देश जारी किया जाता है।

4. उपरोक्त परिदृश्य में, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करना उचित समझता है, रिट याचिका में उठाए गए मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, प्रतिवादी सं.2 को यह निर्देश देते हुए कि वह उपरोक्त मामले का निर्णय कड़ाई से कानून के अनुसार, एक तर्कसंगत एवं सविस्तार आदेश के माध्यम से, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्षकार को कोई अनावश्यक स्थगन दिए बिना, शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से सात माह की अवधि के भीतर करे।

5. उपरोक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

10 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”